Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, Impact Factor: 6.889, Volume 12, No. 02, April-June 2022, pp. 111-114

वर्तमान राजनीति में दबाव समूहों की रचनात्मक भूमिका

सुनील कुमार*

सार

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को समृद्ध और सुरक्षित बनाए रखने के लिए नागरिकों के हितों का उचित प्रतिनिधित्व होना बहुत ही आवश्यक है। दबाव समूहों को किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में आवश्यक बुराई माना गया है, लेकिन एक स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था के विकास के लिए इनका अस्तित्व में बना रहना अति आवश्यक है। जहाँ दबाव समूहों का कार्य केंद्रीय सत्ता को निरंकुश होने से रोकने के साथ प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति व वर्ग की अभिव्यक्ति का साधन भी बनते हैं। लेकिन जब यह हित समूह सामाजिक व्यवस्था से बाहर निकलकर अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक व्यवस्था पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाते हैं तो यह दबाव समूह का रूप ले लेते हैं। भारत में प्राचीन इतिहास से लेकर आज तक दबाव समूह का अस्तित्व किसी ना किसी रूप में बना रहा है। प्राचीन समय में जाति व्यवस्था के स्थान पर वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, जहां पर विभिन्न वर्ग के लोग मिलकर अपने हितों की रक्षार्थ इक्कट्ठे होकर संघर्ष करते रहे हैं। मध्य काल के समय जाति व्यवस्था प्रखर अवस्था में थी जिसने लोगों के बीच स्वहित व स्वार्थी प्रवृत्ति विकसित की। आधुनिक समय में जातिगत समाज के हित संर्वधन की भावना में वृद्धि हुई है। आधुनिक युग की सभी व्यवस्थाओं में दबाव समूह पाए जाते हैं। भारतीय राजनीति में बहुत सारे राजनीतिक दल दबाव समूह से बने है। विविधता वाला देश है क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है जहां पर अलग–अलग प्रकार के जाति, धर्म के लोग निवास करते हैं। इन सभी लोगों के अपने कुछ व्यक्तिगत व विशेष हित होते हैं जिनकी पूर्ति राजनीतिक दल नहीं कर पाते तो ऐसे समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दबाव समूह अस्तित्व में आते हैं और राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव बनाकर उनके हितों की पूर्ति करते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में वर्तमान राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर भी सकारात्मक दबाव समूह के रूप में कई दबाव समूह अपनी रचनात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं यथा– 'किसान मजदूर शक्ति संगठन' अरुणा रॉय के नेतृत्व में दक्षिण एवं दक्षिण मध्य राजस्थान में सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत की जिससे संपूर्ण राष्ट्र में इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के बाद संसद के द्वारा 'सूचना का अधिकार अधिनियम' पारित किया गया।

शब्दकोशः *किसान मजदूर शक्ति संगठन, दबाव समूह, सूचना का अधिकार, प्रखर अवस्था, विभिन्न धर्म।*

प्रस्तावना

वर्तमान राजनीति में दबाव समूहों की रचनात्मक भूमिका

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को समृद्ध और सुरक्षित बनाए रखने के लिए नागरिकों के हितों का उचित प्रतिनिधित्व होना बहुत ही आवश्यक है। दबाव समूहों को किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में आवश्यक बुराई माना गया है, लेकिन एक स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था के विकास के लिए इसका अस्तित्व बना रहना अति आवश्यक है, क्योंकि ये केंद्रीय सत्ता को निरंकुश होने से रोकते हैं तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति व वर्ग की अभिव्यक्ति का साधन भी बनते हैं।

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएसए के बनते ही दबाव समूह अपने अस्तित्व में आ गए थे सबसे पहले यह हित समूह के रूप में उभरे (विशेष वर्ग के लोगों के विशिष्ट हित)। लेकिन जब यह हित समूह सामाजिक व्यवस्था से बाहर निकलकर अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक व्यवस्था पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाते हैं तो यह दबाव समूह का रूप ले लेते हैं।

भारत में प्राचीन इतिहास से लेकर आज तक दबाव समूह का अस्तित्व किसी ना किसी रूप में बना रहा है। प्राचीन समय में जाति व्यवस्था के स्थान पर वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, जहां पर विभिन्न वर्ग के लोग मिलकर अपने हितों की रक्षार्थ इक्कट्ठे होकर संघर्ष करते रहे हैं। मध्य काल के समय जाति व्यवस्था प्रखर अवस्था में थी जिसने लोगों के बीच स्वहित व स्वार्थी प्रवृत्ति विकसित की।

आधुनिक समय में जातिगत समाज के हित संर्वधन की भावना में वृद्धि हुई है। भारतीय संविधान भी इस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए सामाजिक एकता व राष्ट्रीय अखंडता की भावना में वृद्धि के उद्देश्य निहित करता है। सामान्यतः राजनीतिक व सामाजिक समानता की भावना व्यक्ति हित को सामूहिक हित पर प्रधानता करने में सहायता करती है। आधुनिक युग की सभी व्यवस्थाओं में दबाव समूह पाए जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की द्विदलीय व्यवस्था वाले देशों में दबाव समूह अत्यधिक सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं जैसे–अमेरिका। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के पश्चात् भी बहुदलीय पद्धति है इन्हीं कारणों से प्रत्येक दल अपने–अपने सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए कुछ विशिष्ट वर्गों के हितों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में भारतीय राजनीति में बहुत सारे राजनीतिक दल इन्हीं दबाव समूहों की देन है। लेकिन फिर भी भारत एक विविधता वाला देश है जहां पर अलग–अलग प्रकार के जाति, धर्म के लोग निवास करते हैं जो कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के रूप में है। इन सभी लोगों के अपने कुछ व्यक्तिगत व विशेष हित होते हैं जिनकी पूर्ति राजनीतिक दल नहीं कर पाते, तो ऐसे वर्ग समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दबाव समूह अस्तित्व में आते हैं और राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव बनाकर उनके हितों की पूर्ति करते हैं।

राजस्थान की राजनीति में दबाव समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जोकि काफी हद तक सकारात्मक रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान में व्याप्त विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले दबाव समूह की विवेचना करेंगे। राजस्थान की राजनीति में दबाव समूहों ने अहम भूमिका निभाई है, जैसे–स्वयंसेवी संगठन 'किसान मजदूर शक्ति संगठन' ने अरुणा रॉय के नेतृत्व में दक्षिण एवं दक्षिण–मध्य राजस्थान में एक आंदोलन की शुरुआत कर संपूर्ण राष्ट्र में "सूचना का अधिकार कानून" बनाने के लिए सरकार को बाध्य किया। इसी प्रकार खेजड़ली आंदोलन से राजस्थान में "वन संरक्षण कानून" बना। विभिन्न जातिगत आंदोलनों से विभिन्न जातियों को आरक्षण मिला। दबाव समूह का महत्व व उपयोगिता निम्न बिंदुओं के द्वारा रेखांकित की जा सकती है–

- लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूहों को अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है। जैसे–लोकमत को शिक्षित करना, आंकड़े इक्कट्ठे करना, निर्माताओं के पास आवश्यक सूचनाएं पहुंचाना आदि दबाव समूह बखूबी करते हैं ।
- दबाव समूह आंकड़े इक्कट्ठे करके शोध करना और सरकार को अपनी कठिनाइयों से परिचित कराने का काम करते हैं। राजनीति पर प्रशासन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सामाजिक हितों की मांग की पूर्ति करना इनका प्रमुख लक्ष्य होता है।
- दबाव समूह सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाने का कार्य भी करते हैं, क्योंकि वे समय–समय पर लोगों में अपने हितों के प्रति जागरूक करते रहते हैं और समाज व शासन के बीच संतुलन स्थापित करते हैं ।
- लोकतंत्र की व्यवस्था में दबाव समूह व्यक्तिगत हितों का राष्ट्रीय हितों के साथ संबंध स्थापित कर व्यक्ति व सरकार के मध्य संचार के साधन के रूप में कार्य करते हैं।

- दबाव समूह के द्वारा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के प्रतिनिधित्व को सम्मिलित कर क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में भूमिका का निर्वहन करते हैं और सहायता देते है, इसलिए इन्हें 'विधानमंडल के पीछे का विधान मंडल' का जाता रहा है ।
- लोकतंत्र व्यवस्था में लोकतंत्र के पोषक के रूप में राजनीति और प्रशासन दोनों में जनता की सहभागिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, और जनता में प्रतिनिधि के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना जैसे– शासन में क्या होता है? कैसे नीतियां बनती है? कैसे नीतियां क्रियान्वित होती है? शासन की क्या खामियां होती है? इसकी क्या–क्या सफलता हो सकती है? इसकी वास्तविकता क्या है? उन सब के बारे में सूचना जनता तक पहुंचाने का कार्य दबाव समूह बखूबी तरीके से करते हैं।
- विशिष्ट हितों के साथ–साथ दबाव समूह प्रशासन पर भी सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए व्यापक दबाव डालते हैं, नीति निर्माण करके लोकतंत्र में सहायता करते हैं।
- वर्तमान में दबाव समूहों का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि अब उन्हें शासन निर्माता कहा जाने लगा है, कहीं विधानमंडल के पीछे विधानमंडल, कहीं तृतीय सदन और तो कहीं अज्ञात साम्राज्य, कहीं दलों के पीछे रहने वाली जनता आदि के नामों से जाने जाना लगा है।

मेरा शोध विषय राजस्थान राज्य की राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका के संदर्भ में है जो कि भारत के उत्तर–पश्चिम भारत में स्थित है, जहां की जनसंख्या लगभग छह करोड़ के आसपास और क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत में क्रमशः पहला व आठवाँ स्थान रखता है। राजस्थान की राजनीतिक पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न जातिगत आधारित दबाव समूह का वर्चस्व रहा है। राजस्थान के इतिहास में जाट व राजपूत जाति के मध्य संघर्ष व मतभेद विद्यमान मान रहा है, जिससे ये जातियाँ अपने हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर प्राथमिकता देती रही है जिसके फलस्वरूप राजस्थान में विभिन्न समुदायों ने अपने–अपने वर्गों के हित पूर्ति के लिए सामाजिक संगठनों का निर्माण किया जो कि एक जातिगत दबाव समूह के रूप में उभरे। जैसे–सर्व ब्राह्मण महासभा, वैश्य महासभा, जाट महासभा, राजपूत महासभा, गुर्जर महासभा आदि का गठन किया गया जो सरकार के प्रति दबाव समूह के रूप में खड़े हो गए हैं। सन् 1952 में सम्पन्न पहले आम चुनाव से लेकर वर्तमान 2018 तक के विधानसभा चुनावों के परिणामों का विश्लेषण किया जाए तो जातिवाद की शक्ति पर आधारित दबाव समूह की भूमिका स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। चुनावी राजनीति ने राजस्थान में जाति आधारित दबाव समूह की शक्ति व एकता में वृद्धि हुई है किंतु उनकी शक्ति तभी कायम रह सकती है जब समस्त जातियों के लोग उसे समर्थन दें। इसके अलावा कुछ गैर सरकारी संगठन जो कि राष्ट्रीय सतर पर भी सकारात्मक दबाव समूह के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं उनमें 'किसान मजदूर शक्ति संगठन' ने अरुणा रॉय के नेतृत्व में दक्षिण एवं दक्षिण मध्य राजस्थान में सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत की जिससे संपूर्ण राष्ट्र में इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के बाद संसद के द्वारा 'सूचना का अधिकार अधिनियम' पारित किया गया। इस प्रकार दबाव समूह की सकारात्मक भूमिका स्पष्ट दिखाई देती है।

इस शोध के माध्यम से विभिन्न दबाव समूह में जागरूकता पैदा की जायेगी कि वे अपने संकीर्ण विचारों को त्याग देंगें और व्यापक विचारधारा के साथ राज्य की राजनीति में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस शोध में यह परिकल्पना और की गई है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो फिर हमे लोगों के दोनों पहलूओं पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हो सकता है हम किसी चीज को एककोण से देखें तो भद्दी लगे और दूसरे कोण से देखेंगे तो शायद वही चीज सुंदर लगे, इसलिए हमें दबाव समूह के नकारात्मक पहलू के बजाय सकारात्मक पहलू पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इसलिए हमें समाज के हिसाब से व्यवस्था में बदलाव करते रहना चाहिए। प्रस्तावित शोध के माध्यम से यह देखने का प्रयास किया गया कि जब राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह प्रारंभ से सक्रिय रहे और उन्हें नकारात्मक रहे दृष्टि से देखा गया, क्यों ना अब नई सदी में इनकी संरचनात्मक व प्रकार्यात्मक स्वरूप में बदलाव कर इनकी भूमिका को राजनीति में सकारात्मक रूप से प्रस्तुत कर, एक स्वस्थ राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। यही मेरे शोध विषय का मूल उद्देश्य है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कीवीओ (1964), "पॉलिटिक्स पार्टीज एण्ड प्रेशर ग्रुप", क्रोवेल पब्लिकेशन, न्यूयॉर्क
2. गाबा, ओम प्रकाश (2015), तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा, मयूर पेपर बेक्स प्रकाशक, जयपुर।
3. चौधरी, लाखाराम (2016), भारत में चुनावी राजनीति एवं चुनाव सुधार के प्रयास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
4. मंगलानी, रूपा, भारतीय शासन एवं राजनीति, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
5. मॉरिस, जॉन (1967), दी गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, हचिंसन एंड कम्पनी पब्लिशर, लंदन।
6. महाजन, वी.डी., पॉलिटिकल थ्योरी, एस.चांद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली
7. जॉर्ज, ए. हैलरी (1955), डेफिनेशन ऑफ कम्यूनिटी : एरियाज ऑफ एग्रीमेन्ट सोशलॉजी, वॉल्यूम–22.
8. फड़िया, बी.एल., इंडियन गर्वनमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स, साहित्य भवन, आगरा।
9. Bombwall, K.R. (1998). "Regional Parties in Indian Politics" in S.Bhatnagar and Pradeep Kumar (ed.) Regional Political Parties in India. New Delhi: Ess Ess Publishers.
10. Alam, Javeed (2004). Who Wants Democracy? New Delhi: Orient Longman.
11. Odyguard, Pressure Politics, Published Online by Cambridge University Press: August, 2014.

♦❐♦